

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्या: 108/2016 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

श्रीयाराम पुत्र दीपसिंह जाति गुर्जर निवासी कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

अपीलान्त

बनाम

1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी राधेश्याम जाति वैश्य निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर।

असल रैस्पोंडेन्ट

3. शेरसिंह } पुत्रान दीपचंद जाति गुर्जर निवासी कमालपुरा तहसील
4. श्रीराम } तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

तरतीवी रैस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 12.3.2016 व इन्तकाल नम्बर 1908 वाकै ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।



रूपरिखित :
श्री तालेराम वकील अपीलान्त।
श्री पंकज कुमार वकील रैस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक : 14.9.2018

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार भुसावर की आज्ञा दिनांक 12.3.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह फैसला तहसीलदार भुसावर दिनांक 12.3.2016 इन्तकाल नम्बर 1908 वाकै ग्राम कमालपुरा तहसील भुसावर खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि यह इन्तकाल दौराने मुकदमा भरा गया है क्यों कि जो डिक्री एसडीओ साहब भुसावर ने दिनांक 5.2.2016 को दी थी जिसके तहत यह इन्तकाल भरा है व डिक्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पदेन भू प्रबन्ध अधिकारी के यहां पेडिंग है। लायक अदालत ने कोई मौके की जांच नहीं की है और अपीलान्त का कब्जा एन0एच0 11 की तरफ है। अपीलान्त को इस फैसले का कोई इल्म नहीं होने दिया और रैस्पोंड संख्या 1 से मिलकर तहसीलदार साहब ने दिया है जो कतई

की जावे। विवादित आराजी के संबध में आज तक कोई स्टे नहीं है।
 न्यायाधीश पर भी कोई स्टे उपलब्ध नहीं है। म्यूटेशन डिक्री के अनुरूप ही भरा
 है। अन्त में वकील रैस्पोजेन्ट द्वारा अपील अपीलान्त खारिज फरमाते हुये
 अदालत द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1908 दिनांक 12.3.
 2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील अपीलान्त की बहस तर्कों पर मनन किया तथा
 पत्रावली का अवलोकन किया गया साथ ही वकील रैस्पोजेन्ट द्वारा प्रस्तुत
 न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण
 के कॉलम नम्बर 14-16 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि अपीलाधीन
 नामान्तरकरण निर्णय/डिक्री न्यायालय एस0डी0ओ0 निर्णय दिनांक 5.2.2016 की
 पालना में मुताबिक हुक्मन आदेश अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1908 बाद
 जांच स्वीकृत किया गया है ऐसे में नामान्तरकरण की कार्यवाही को विधिविरुद्ध
 नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस डिक्री/निर्णय के
 आधार पर स्वीकृत किया गया है उसकी वैधता सक्षम न्यायालय द्वारा तय नहीं
 हो जाती नामान्तरकरण की कार्यवाही को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी
 स्थिति में 75 एलआरएक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत नामान्तरकरण की अपील में उस
 आधार (निर्णय/डिक्री) का परीक्षण किया जाना न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार
 होने के कारण मुनासिब नहीं रहता है। अपीलान्त की ओर से ऐसा कोई
 प्रमाण भी अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके
 कि उक्त निर्णय/डिक्री दिनांक 5.2.2018 सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा
 चुका हो अथवा दौराने स्वीकृति अपीलाधीन नामान्तरकरण किसी सक्षम अदालत
 का स्थगन आदेश प्रभावी हो। अर्थात् वर्तमान में निर्णय दिनांक 5.2.2016
 आस्तित्व में है और इस निर्णय/डिक्री के आस्तित्व में रहते हुये उसके आधार
 पर स्वीकार किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में हम किसी प्रकार का कोई
 हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलान्त खारिज
 योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त आधारहीन होने के
 कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार भुसावर द्वारा स्वीकृत
 अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1908 दिनांक 12.3.2016 में कोई विधिक त्रुटी
 न होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।



अतः - स्वीकृत है।
 डिक्री के अन्तर्गत म्यूटेशन नही हुआ है
 अतः अदालत द्वारा उक्त न्यायिक

— २९ न्यायिक आदेश नहीं था ताकि उक्त न्यायिक आदेश